

कम उत्पादन और ज्यादा मांग के कारण कीमतें बढ़ीं

चीनी की कीमत 70 प्रति किलो तक पहुंची, केंद्र ने माना कि उत्पादन घटा है



एजेंसी - नई दिल्ली, देश में चीनी की कीमत 70 प्रति किलो तक पहुंचने के बाद, केंद्र ने साफ किया है कि यह स्थिति इस साल चीनी का उत्पादन कम होने के कारण पैदा हुई है। चीनी का उत्पादन 343 लाख टन के अनुमान के मुकाबले सिर्फ 306

लाख टन हुआ, जबकि घरेलू मांग सिर्फ 280 से 285 लाख टन है। सरकार ने कहा कि चीनी की कीमतों का इथेनॉल उत्पादन से कोई लेना-देना नहीं है।

भारत में त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है और इसी समय, आलोककों ने चीनी की कीमतें

बढ़ने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका दावा है कि कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि सरकार चीनी की सप्लाई इथेनॉल की ओर मोड़ रही है। केंद्र ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। केंद्र ने कहा कि 2022-23 में इथेनॉल उत्पादन में चीनी का

योगदान 12 प्रतिशत था, जो 2025-26 में घटकर नौ प्रतिशत हो गया है; इसके हिसाब से यह हिस्सा 4 मिलियन टन से घटकर 2.8 मिलियन टन हो गया है। इस तरह, कुल चीनी उत्पादन का सिर्फ दसवां हिस्सा ही इथेनॉल के लिए जाता है। सरकार ने साफ किया है कि चीनी की कीमतों में यह बढ़ोतरी कम उत्पादन और ज्यादा मांग के कारण हुई है। चीनी की कीमतें सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़ी हैं। वे पूरी दुनिया में बढ़ी हैं। अनुमान है कि 2026-27 में कम से कम 3.3 मिलियन टन चीनी की कमी होगी। 30 जून को चीनी की कीमत 474 प्रति टन थी, जो 20 अगस्त को बढ़कर 552 प्रति टन हो गई। इस तरह, दो महीनों में चीनी की कीमत 16 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गई है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरकार का साफ मानना ? है कि कुछ चीनी मिलों

की व्यापारियों द्वारा जमाखोरी के कारण चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। इसे रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 1 अगस्त से 30 नवंबर तक चीनी डीलरों पर 400 टन की स्टॉक लिमिट लगाई गई है। 1 सितंबर से, थोक खरीदार 15 दिनों

की खपत से ज्यादा चीनी नहीं खरीद पाएंगे। केंद्र और राज्य की टीमों मिलकर मिलों में स्टॉक की जांच कर रही हैं। उनका मकसद जमाखोरी और बनावटी कमी को रोकना है। सरकार ने त्योहारों के मौसम में चीनी की कमी से बचने

के लिए 10 लाख टन चीनी के आयात की भी इजाजत दी है। इसके साथ ही, चीनी मिलों में नया पेराई सीज़न 15 दिन पहले शुरू करने के लिए कहा गया है, ताकि बाज़ार में चीनी की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे। इस

वजह से अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य से ज्यादा होने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक, आमतौर पर अक्टूबर में तीन से चार लाख टन चीनी का उत्पादन होता है। इस बार यह 10 लाख टन तक पहुंच सकता है।

एयरपोर्ट पर लंबी लाइनों से छुटकारा

बोर्डिंग पास पर स्टैम्प लगाने की प्रक्रिया स्वतः

एजेंसी - नई दिल्ली, भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत की खबर है। अब इंटरनेशनल यात्रियों को इमिग्रेशन काउंटर पर अपने बोर्डिंग पास पर फिजिकली स्टैम्प लगवाने की जरूरत नहीं होगी।

गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने फैसला किया है कि 1 सितंबर, 2026 से देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास पर स्टैम्प लगाने की प्रक्रिया हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। अब यात्री अपने स्मार्टफोन पर डिजिटल ई-बोर्डिंग पास दिखाकर आसानी से इमिग्रेशन क्लर्क से मिल सकेंगे।

बोर्डिंग पास पर स्टैम्प लगाना क्यों बंद किया गया ? इमिग्रेशन ब्यूरो को यात्रियों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि स्टैम्प लगाने की प्रक्रिया से सिस्टम में देरी हो रही थी।



हर बोर्डिंग पास पर स्टैम्प लगाने की वजह से यात्रियों का काउंटर पर काफी समय बर्बाद होता था। कई बार स्टैम्प ठीक से नहीं लगता था या गलत जगह लग जाता था, जिससे बोर्डिंग गेट पर सिक्क्योरिटी चेक के दौरान उसे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी।

1 सितंबर से बदले सिस्टम के मुख्य नियम लागू होने की तारीख 1 सितंबर, 2026 से लागू होने का क्षेत्र-देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट

नया फीचर- मोबाइल पर डिजिटल ई-बोर्डिंग पास मान्य होगा। प्रिंटेड पास रखने वाले प्रिंटेड बोर्डिंग पास रखा जा सकता है, लेकिन उस पर कोई स्टैम्प नहीं लगाया जाएगा अधिकारियों ने साफ किया है कि जो यात्री अभी भी प्रिंटेड बोर्डिंग पास रखना चाहते हैं, वे रख सकते हैं। बस बदलाव यह है कि इमिग्रेशन अधिकारी अब उस कागज पर कोई स्टैम्प नहीं लगाएंगे। यह हवाई यात्रा को पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल

बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारतीय पासपोर्ट धारकों के देश से बाहर जाने और वापस आने पर पासपोर्ट पर फिजिकली स्टैम्प लगाने की प्रक्रिया को भी खत्म करने की योजना है। इसके लिए अभी कुछ चुने हुए एयरपोर्ट पर एक पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद, जल्द ही पूरे देश के एयरपोर्ट पर पासपोर्ट पर बिना स्टैम्प वाला ई-गेट सिस्टम पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।

पहलगाम हमले के मामले में हाफज़ि सईद की मुश्किलें बढ़ीं

भारत हाफज़ि सईद को पाकिस्तान से खींचकर लाएगा

एजेंसी - नई दिल्ली, लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख और खतरनाक आतंकवादी हाफज़ि मुहम्मद सईद पर शिकंजा कसता जा रहा है। भारत ने 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के मामले में हाफज़ि सईद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। स्पेशल कोर्ट द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) अब डिप्लोमैटिक चैनलों के जरिए लाहौर में सईद को कोर्ट का समन भेजने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, विदेश मंत्रालय (MEA) पाकिस्तान को समन भेजेगा।

जुलाई 2026 में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में, NIA ने पहलगाम हमले की साजिश में हाफज़ि सईद को आरोपी बनाया है। एजेंसी ने उसे व्यक्तिगत रूप से और लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट (LRF) के नेता के तौर पर आरोपी बनाया है। चार्जशीट में उस पर भारत के खिलाफ साजिश रचने और युद्ध छेड़ने में भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है।

इसके बाद, जम्मू की एक स्पेशल कोर्ट ने जुलाई में हाफज़ि सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। अब, समन तामील कराने की प्रक्रिया को इस दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सईद को कोर्ट के सामने पेश होने का औपचारिक मौका मिले। अगर समन के बावजूद वह कोर्ट में पेश नहीं होता



है और तय कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। भारत उन मामलों में नए क्रिमिनल लॉ के तहत कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है जिनमें आरोपी देश से बाहर है और उसकी गिरफ्तारी या प्रत्यर्पण संभव नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (ICSC) की धारा 356 में कुछ खास शर्तों के तहत आरोपी पर मुकदमा चलाने का प्रावधान है; इसमें उसकी अनुपस्थिति में जांच, दायल या फैसले का प्रावधान है। सरकार इस बात पर ज़ोर दे रही है कि सईद के खिलाफ उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा शुरू करने से पहले सभी ज़रूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। लाहौर में कोर्ट का समन तामील कराने की कोशिश इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

इससे भारत को एक आधिकारिक रिकॉर्ड भी मिलेगा कि उसने आरोपी को

भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने का मौका देने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी और डिप्लोमैटिक चैनलों का इस्तेमाल किया। पहलगाम हमले के मामले में लश्कर प्रमुख हाफज़ि सईद के खिलाफ मजबूत कानूनी रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया का भारत-पाकिस्तान संबंधों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी असर पड़ सकता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस कदम से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई मजबूत हो सकती है।

इसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) से जुड़ी चर्चाओं में भी किया जा सकता है। भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर अपनी ज़मीन पर मौजूद आतंकवादी नेताओं के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाता रहा है।

पाकिस्तान का कहना है कि टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद हाफज़ि सईद हिरासत में है। हालांकि, भारतीय एजेंसियां ? उसे पहलगाम हमले समेत बड़ी आतंकी साजिशों से जोड़ती रही हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा प्रक्रिया का व्यापक मकसद उन कानूनी बाधाओं को दूर करना है जिनसे विदेश में रह रहे या कानूनी प्रक्रिया से बच रहे आतंकी आरोपियों को फायदा मिल सकता है। हाफज़ि सईद को समन जारी करने से लेकर आगे की संभावित कार्रवाई तक, भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पहलगाम हमले के मामले में हर ज़रूरी कानूनी कदम रिकॉर्ड पर हो। अगर वह अदालत के सामने पेश नहीं होता है, तो उसकी अनुपस्थिति में मामले को आगे बढ़ाने का आधार तैयार किया जा सकता है।

मुंबई में फूड सेफ्टी को लेकर सख्ती

मैकडॉनल्ड्स समेत 13 फूड आउटलेट्स के लाइसेंस सस्पेंड

एजेंसी - मुंबई, महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (स्वच्छ) ने फूड सेफ्टी और साफ-सफाई के नियमों के कथित उल्लंघन के लिए राज्य में 13 फूड आउटलेट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। इनमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब और दक्षिण मुंबई में मैकडॉनल्ड्स का एक आउटलेट शामिल है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह घोषणा की।

मई में सीनियर अफसर तुकाराम मुंडे के स्वच्छ कमिशनर का पद संभालने के बाद से, स्वच्छ फूड सेफ्टी और दूसरे नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, स्वच्छ ने हाल ही में चलाए गए स्पेशल ड्राइव के दौरान राज्य भर में कुल 89 होटलों, रेस्तरां और फूड शॉप्स का निरीक्षण किया।

इनमें से 71 फूड आउटलेट्स को सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए, जबकि 13 प्रतिष्ठानों के



फूड बिज़नेस लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। बयान के अनुसार, 19 अगस्त को किए गए निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रेडियो क्लब ने फूड सेफ्टी और साफ-सफाई के नियमों का उल्लंघन किया था। क्लब को सस्पेंशन की अवधि के दौरान खाने-पीने की चीजों की खरीद, बिक्री और वितरण रोकने का निर्देश दिया गया है।

क्लब की रसोई में बड़ी संख्या

में ज़ुदा मक्खियाँ और मरे हुए कॉकोरोच पाए गए। खाने-पीने की चीजें सीधे फर्श पर रखी हुई मिलीं और जहाँ खाना तैयार किया जा रहा था, वहाँ खत से प्लास्टिक की शीट फटी हुई देखी गई।

दक्षिण मुंबई के कोलाबा में मेट्रो हाउस में हार्डकैसल रेस्तरां प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां का लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से

सस्पेंड कर दिया गया है। 19 अगस्त को किए गए दोबारा निरीक्षण में पाया गया कि पहले जारी किए गए सुधार नोटिस में बताई गई 20 कमियों में से 18 कमियों को ठीक नहीं किया गया था। अधिकारियों ने रेस्तरां में कई कमियाँ देखीं, जिनमें खराब टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस, ज़ुदा कॉकोरोच, गंदगी और खाने का कचरा शामिल था।



संक्षिप्त

समाचार

प्रिंस हैरी शाही भूमिकाओं के बिना ब्रिटेन लौटेंगे; भारतीय महिला को इसाइल में अच्छी नागरिकता सम्मान

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन ने यूनाइटेड किंगडम लौटने का फैसला किया है। हालांकि, वे शाही परिवार के कामकाजी सदस्यों के रूप में अपनी भूमिकाएं फिर से शुरू नहीं करेंगे। किंग चार्ल्स को रविवार को इस निर्णय के बारे में सूचित किया गया। हालांकि, पिछले महीने दंपती की यूके यात्रा के दौरान उन्हें इस बारे में नहीं बताया गया था। डेली टेलीग्राफ ने यह खबर सबसे पहले प्रकाशित की है। अक्सर के अनुसार, हैरी और मेघन के बच्चे, प्रिंस आर्ची (7) और प्रिंसेस लिलिबेट (5), ब्रिटिश स्कूलों में पहले ही दाखिला ले चुके हैं। वे सितंबर में अपनी कक्षाएं शुरू करेंगे। यह निर्णय दंपती द्वारा अपनी शाही जिम्मेदारियां छोड़ने के छह साल से अधिक समय बाद आया है। उन्होंने आर्कबर्क मीडिया अनुबंधों को आगे बढ़ाने के लिए फैलिफॉर्निया का रुख किया था। ब्रिटेन लौटने से किंग चार्ल्स को अपने पोते-पौतियों से अधिक मिलने का अवसर मिलेगा। किंग चार्ल्स एक अज्ञात प्रकार के कैंसर का इलाज करा रहे हैं। दंपती ने छह साल से अधिक समय पहले अपने शाही कर्तव्यों को त्याग दिया था। वे फैलिफॉर्निया में बस गए थे। इस वापसी से परिवार के संबंधों में मजबूती आ सकती है।

इसाइल में देखभाल करने वाली भारतीय महिला को अच्छी नागरिकता का सम्मान

यरुशलम, एजेंसी। इसाइल पुलिस ने एक भारतीय महिला को अच्छी नागरिकता के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया है। देखभाल करने वाली इस महिला ने कार्मेल क्षेत्र में 95 वर्षीय होलोकॉस्ट पीडित को ठगी के प्रयास से बचाया था। बुधवार को तटीय जिला पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में हाइफा पुलिस स्टेशन के जांचकर्ताओं ने हीरा (हीराबेन) को यह प्रमाण पत्र प्रदान किया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, हीराबेन उस बुजुर्ग महिला की नर्सिंग देखभालकर्ता यानी कैरगिवर के रूप में काम कर रही हैं। इजरायल में कुछ ही महीने रहने के बावजूद, हीराबेन ने सुझबुझ और साहस का परिचय दिया। उन्होंने महिला को एक कथित धोखाबाज से बचाया, जो वलैलिंट हेल्थ सर्विसेज की नर्स बनकर उनके अपार्टमेंट में आया था। देखभालकर्ता ने शांत रहते हुए घटना को दर्ज किया, संदिग्ध को बुजुर्ग महिला के पास जाने से रोका और पुलिस को सूचित किया। इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और संदिग्ध की हिरासत दो दिन पहले कानूनी कार्रवाई पूरी होने तक बढ़ा दी गई थी। जांचकर्ता नोफर पाज ने बुजुर्ग महिला और उनके परिवार की उपस्थिति में हीराबेन को धन्यवाद दिया।

सफारी के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश, पांच अमेरिकी समेत सात लोगों की मौत

नैरोबी, एजेंसी। केन्या के उत्तरी हिस्से में बुधवार सुबह सफारी के दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस और अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, मृतकों में पांच अमेरिकी नागरिक शामिल थे। हेलीकॉप्टर सुबह 9-13 बजे लॉइसाबा कंजरवेसी से साम्बुरु काउंटी के इवासी न्यिरो इलाके की ओर जा रहा था। केन्या नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, हेलीकॉप्टर में कुल सात लोग सवार थे। इनमें छह यात्री और एक पायलट था। उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। साम्बुरु के पुलिस कमांडर डेविड नकोरोई ने बुधवार देर शाम पुष्टि की कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई है। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि मृतकों में पांच अमेरिकी नागरिक थे। अमेरिकी दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और पीडितों से जुड़े लोगों को जरूरी कांसुलर सहायता उपलब्ध करा रहा है। मृतकों की आधिकारिक पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित एक स्थानीय टीवी स्टेशन ने बताया कि मृतकों में जोस सुआरेज भी शामिल थे, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी और वह टेलेमुंडो के फ्लोरिडा स्थित कई स्टेशनों के अध्यक्ष और महाप्रबंधक थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार, हेलीकॉप्टर माउंट ओलोलीछे की तलहटी में स्थित एक दुर्गम और ऊबड़-खाबड़ इलाके में गिरा। यह स्थान पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। हेलीकॉप्टर स्थानीय कंपनी लीडो लॉरी हेलीकॉप्टर्स का था और वाटर उड़ान के तहत यात्रियों को ले जा रहा था। सफारी कंपनी एडबिर्गोड के साथ यात्रा कर रहे लोगों के लिए यह उड़ान संचालित की गई थी। ट्रॉपिक एयर केन्या ने बताया और बचाव अभियान में मदद के लिए अपने दो हेलीकॉप्टर भेजे। केन्या रेड क्रॉस की आपातकालीन टीम भी बहु-एजेंसी राहत अभियान में शामिल हुई।

कौन हैं अमेरिका की एफडीए प्रमुख बनने जा रहीं हेड्डी ओवरटन, ट्रंप ने किया नामित, विवादों से भी रहा है नाता

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की वरिष्ठ अधिकारी डॉ. हेड्डी ओवरटन को खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए का अगला आयुक्त बनाने के लिए नामित किया है। अगर अमेरिकी सीनेट उनकी नियुक्ति को मंजूरी देती है, तो वह इस बेहद महत्वपूर्ण संस्था की जिम्मेदारी संभालेंगी। एफडीए/अमेरिका में दवाओं, वैक्सीन, चिकित्सा उपकरणों और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और नियमन से जुड़े बड़े फैसले करता है। ओवरटन फिलहाल व्हाइट हाउस के चेरलू नीति परिषद में उपनिदेशक के पद पर हैं और ट्रंप प्रशासन की स्वास्थ्य नीतियों को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाती रही है।

ओवरटन की पढ़ाई और करियर कितना मजबूत : हेड्डी ओवरटन मेडिकल डॉक्टर हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको से मेडिकल की पढ़ाई की। इसके बाद डॉसर्स हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी का प्रशिक्षण लिया और क्लिनिकल जांच से जुड़ी उच्च शिक्षा भी हासिल की। ट्रंप प्रशासन में आने से पहले

वह कंजर्वेटिव थिंक टैंक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट में मुख्य नीति अधिकारी के रूप में काम कर चुकी हैं। यानी उनका अनुभव केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य नीति और राजनीतिक प्रशासन से भी जुड़ा रहा है।

ट्रंप के भरोसेमंद लोगों में कैसे शामिल हुई : दूसरे कार्यकाल में ओवरटन ट्रंप की कई स्वास्थ्य योजनाओं में उनके साथ दिखाई दी हैं। दवा की कीमत कम करने, नई दवाओं को तेजी से मंजूरी देने और स्वास्थ्य नीति में बदलाव से जुड़े कई कार्यक्रमों में उन्होंने भूमिका निभाई है। ट्रंप ने उनके नाम की घोषणा करते हुए उन्हें बेहद सक्षम और भरोसेमंद अधिकारी बताया तथा तेज रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने भी ओवरटन के फैसले लेने की क्षमता और प्रशासनिक अनुशासन की तारीफ की है।

वैक्सीन नीति को लेकर क्यों उठे सवाल : ओवरटन की नियुक्ति का



सबसे विवादित पक्ष उनकी वैक्सीन नीति से जुड़ी भूमिका है। हाल में वह उस कार्यक्रम में ट्रंप के साथ खड़ी थीं, जिसमें बच्चों के टीकाकरण से जुड़ी नीति में बड़े बदलावों की घोषणा की गई थी। इसमें खरसा, कण्ट्रामा और रूबेला यानी एपएमआर वैक्सीन को अलग-अलग टीकों में बांटने की योजना भी शामिल थी। चिकित्सा जागत के कई लोगों ने इस नीति पर सवाल उठाए हैं। इसी वजह से ओवरटन की एफडीए में संभावित भूमिका को लेकर वैज्ञानिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहस तेज हो गई है।

गर्भपात की दवाओं पर क्या है ओवरटन का रुख : ओवरटन गर्भपात की दवाओं को लेकर भी सख्त रुख रखती हैं। वह ऐसी दवाओं की उपलब्धता और ऑनलाइन इस्तेमाल से जुड़ी मौजूदा व्यवस्था की आलोचना कर चुकी हैं। अगर सीनेट से उनकी नियुक्ति मंजूर होती है, तो ख़ूब के सामने गर्भपात की दवाओं से जुड़े नियमों की समीक्षा भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। अमेरिका में गर्भपात को लेकर पहले से ही राजनीतिक और कानूनी विवाद चल रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर ओवरटन के फैसलों पर खास नजर रहेगी।

एफडीएको संभालते ही कितन बड़ी चुनौतियों का सामना होगा : ओवरटन ऐसे समय एफडीए की कमान संभाल सकती हैं, जब संस्था पहले ही नेतृत्व और कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी चुनौतियों से गुजर रही है। पूर्व आयुक्त डॉ. मार्टी मकारी ने मई में पद छोड़ दिया था। उनके कार्यकाल में ई-सिगनेचर, गर्भपात की दवाओं और नई दवाओं की मंजूरी जैसे मुद्दों पर विवाद रहे। एफडीए में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के जाने से

भी संस्था पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में नई प्रमुख से प्रशासनिक स्थिरता और जनता का भरोसा बहाल करने की उम्मीद होगी।

क्या दवाओं की मंजूरी का तरीका भी बदल सकता है : एफडीए की एक बड़ी जिम्मेदारी नई दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की जांच तथा मंजूरी देना है। ट्रंप प्रशासन तेज मंजूरी और चिकित्सा नवाचार को बढ़ावा देने की बात करता रहा है। दूसरी ओर, एफडीए से जुड़े वैज्ञानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सुरक्षा मानकों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत पर जोर देते हैं। ओवरटन को इन दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। खासकर दुर्लभ बीमारियों की दवाओं, जैव-तकनीकी उत्पादों और नई चिकित्सा तकनीकों से जुड़े फैसले उनके सामने महत्वपूर्ण चुनौती होंगे। एफडीए केवल दवाओं और वैक्सीन तक सीमित नहीं है। खाद्य सुरक्षा भी उसकी जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन में स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने अल्ट्राप्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को लेकर लगातार सवाल उठाए हैं।

गंगा जल पर फिर तनातनी: गारंटी प्रावधान मांगने की तैयारी में बांग्लादेश, क्या भारत से बिगड़ेंगे रिश्ते



भविष्य की जल-बंटवारा संधियों में सूचना के अधिकार से जुड़ा प्रावधान शामिल करने की जरूरत बताई। उन्होंने 1977 की गंगा संधि में मौजूद 'गारंटी प्रावधान' को फिर शामिल करने की मांग की। यह प्रावधान 1996 की संधि में नहीं रखा गया था। गारंटी प्रावधान का मतलब है कि निचले हिस्से वाले देश को पानी की न्यूनतम मात्रा मिलने की गारंटी हो। आधारी है। सूखे मौसम में नदी का प्रवाह अब ज्यादा अनिश्चित हो गया है। बांग्लादेश पर्यावरण से जुड़े प्रावधानों को भी अपयोज मानता है। वह ऊपरी

हिस्से में पानी की निकासी, नदी के स्वास्थ्य, बढ़ती लवणता और पारिस्थितिक प्रवाह को भी चर्चा में शामिल करना चाहता है।

क्या फरक्का बैराज फिर बनेगा विवाद का केंद्र : भारत-बांग्लादेश जल संबंधों में फरक्का बैराज लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। पश्चिम बंगाल में भारत द्वारा बनाए गए इस बैराज का उद्देश्य गंगा के पानी के एक हिस्से को हुगली नदी तंत्र की ओर मोड़ना है। बांग्लादेश में इसे लेकर लंबे समय से चिंता रही है कि इससे सूखे मौसम में नीचे की ओर पानी का प्रवाह कम होता है। अनी ने कहा कि बांग्लादेशी लोग लंबे समय से फरक्का बैराज को 'मौत का जाल' मानते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि फरक्का के बाद भारत ने गंगा पर बैराज और करीब 900 तटबंध बनाए, जिससे दोनों देशों के संबंधों पर दबाव पड़ा।

भारत का रुख क्या : भारत का कहना है कि फरक्का बैराज बांध नहीं, बल्कि पानी को मोड़ने वाली संरचना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इसके द्वारा की व्यवस्था के जरिए गंगा के करीब 40,000 क्युसेक पानी को फरक्का नहर में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी पानी बांग्लादेश की ओर बहता रहता है। भारत यह भी कहता है कि समझौते के तहत जल प्रवाह का आंकड़ा संयुक्त नदी आयोग के जरिए बांग्लादेश के साथ नियमित रूप से साझा किया जाता है। बांग्लादेश और

भारत के बीच 54 प्रमुख नदियां साझा हैं। गंगा दोनों देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीमा-पार नदियों में से एक है। जल बंटवारे और नदी से जुड़े मुद्दों पर दोनों देश संयुक्त नदी आयोग के जरिए बातचीत करते हैं।

क्या भारत जल्द शुरू करेगा नई संधि पर बातचीत : जुलाई में भारत की विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर बिना और देरी के बातचीत शुरू करने को कहा था कि समिति ने सिफारिश की थी कि बातचीत में नए जलवैज्ञानिक आंकड़ों, जलवायु अनुमानों और पश्चिम बंगाल तथा बिहार की विन्ताओं को ध्यान में रखा जाए। भारत सरकार ने फरवरी में संसद को बताया था कि संधि के नवीनीकरण को लेकर बांग्लादेश के साथ बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। सरकार ने यह भी कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार सहित संबंधित पक्षों से मिले सुझावों को भारत का रुख तय करते समय ध्यान में रखा गया है। अनी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब इससे दो दिन पहले उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश तीस्ता नदी के लंबे समय से लंबित जल-बंटवारा समझौते को लेकर भारत के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध खराब नहीं करना चाहता। उन्होंने भारत से अपने हितों के साथ बांग्लादेश के हितों की भी ध्यान में रखने की अपील की थी।

अमेरिका में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, भागवत के यूएस दौरे पर यूएससीआईआरएफ सख्त; बोला- संघ नेताओं को न मिले सम्मान



वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता पर काम करने वाली सलाहकार संस्था यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ) के अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने अमेरिकी सरकार से अपील की है कि वह आरएसएस नेताओं को राजनयिक सम्मान न दे और न ही उनके साथ किसी तरह की हाई-लेवल मीटिंग करे। यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित अमेरिका दौरे से पहले आया है। वहीं, भागवत ही यूएससीआईआरएफ की रिपोर्टों को पक्षपातपूर्ण और वैचारिक पूर्वाग्रह पर आधारित बताते हुए खारिज कर चुका है। आरएसएस नेताओं से दूरी बनाने की अपील यूएससीआईआरएफ के चेयरमैन

आसिफ महमूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य हैं। उन्होंने आरएसएस को एक %अंब्रेला ऑर्गनाइजेशन यानी ऐसा मुख्य संगठन बताया, जिसके सदस्यों की संख्याओं पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले करने के आरोप लाते रहे हैं। महमूद की ये टिप्पणियां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे से कुछ हफ्ते पहले सामने आई हैं। भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में अमेरिकन हिंदूज़ फॉर एग्रीजमेंट एंड डायलॉग की ओर से आयोजित

यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन (एकता का उत्सव) में शामिल होने वाले हैं। आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध की मांग यूएससीआईआरएफ कमिशनर जीन मिल्स ने कहा कि आरएसएस नेताओं को, भले ही वे भारत सरकार से जुड़े हों, हाई-लेवल मीटिंग या राजनयिक सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बजाय, अमेरिकी सरकार को उन आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान देना चाहिए, जो फ्रीडम ऑफ रिलिजन ऑर बिलीफ यानी धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन

के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। यूएससीआईआरएफ ने आसिफ महमूद और जीन मिल्स की इन टिप्पणियों को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। महमूद ने आरएसएस को लेकर वक्ता कहा महमूद ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य हैं। यह भारत का एक मुख्य संगठन है, जिसके सहयोगी समूहों ने ईसाइयों और मुसलमानों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। अब आरएसएस नेता मोहन भागवत अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। हिंदूज़ फॉर यूनिवर्सल सेलिब्रेशन में भागवत के दौरे को मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ आरएसएस नेटवर्क से जुड़े हिंसा के आरोपों से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

ईरान पर होगी सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई: ट्रंप ने दी धमकी, मदद करने वाले देशों को चेताया; क्या बढ़ेगा तनाव

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त आर्थिक कार्रवाई की धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का सबसे बड़ा मौका दिया गया था। लेकिन उसने इसे गंवा दिया।

ट्रंप ने कहा, इस्लामी गणराज्य ईरान को किसी समझौते के लिए मुझसे ज्यादा बड़ा मौका किसी ने नहीं दिया। दुख की बात है कि उन्होंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। इसलिए अब मैं किसी भी देश के खिलाफ आज तक की सबसे कड़ी आर्थिक कार्रवाई की घोषणा कर रहा हूँ। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना खस्र हो चुकी है। उसकी वायु सेना नष्ट हो गई है। उसकी सैन्य फैक्टरियां मलबे में बदल गई हैं। ईरान की मुद्रा बेकार हो गई है और देश बेहद कमजोर स्थिति में है।

ईरान की मदद करने वाले देशों पर भी कार्रवाई : ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद देगा, उसे भी बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसमें वित्तीय संस्थाएं, कारोबार, हवाई अड्डे और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने तेल की तस्करी, स्वेप लाइन, नकद लेनदेन, एक्सचेंज हाउस, जहाजों के पंजीकरण और ईरान की मदद करने वाली छिपी हुई (शेल) कंपनियों को तुरंत रोकने की बात कही।

सहयोगी देशों से अमेरिका के साथ आने की अपील : ट्रंप ने इसे ईरान के खिलाफ बड़े आर्थिक हमले का दिन बताया। उन्होंने अमेरिका के सहयोगी देशों से ईरान को अलग-थलग करने और उसके खतरे को खत्म करने में साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईरान इस समय बेहद कमजोर स्थिति में है।



उन्होंने दावा किया कि ये ऐतिहासिक कदम ईरान को और दुनियाभर में आतंक फैलाने की उसकी क्षमता को बुरी तरह कमजोर कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होंगे।

अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाया : अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के पिछले हफ्ते इसी तरह बयान दिया था। बेसेंट ने कहा था कि अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिशें बढ़ाएगा। इस रणनीति में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी भी शामिल है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय %ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी% नाम से प्रतिबंध अभियान भी चला रहा है। इसका मकसद लक्षित कार्रवाई के जरिये ईरान के पैसे जुटाने के स्रोतों को बंद करना है। युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इराक के हमलों के साथ हुई। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने ईरान को सैन्य उपकरण और ड्रोन से जुड़ी तकनीक दी है। वहीं, चीन लगातार ईरान से तेल खरीद रहा है। चीन ने ईरान के साथ कारोबारी रिस्ते बनाए रखे हैं और उसे कूटनीतिक समर्थन भी दिया है।

गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फूड सेफ्टी ब्रांच होटलों और रेस्टोरेंट की जांच कर रही है

पट्टी वड़ा पाव के रजिस्ट्रेशन को 7 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वहां चूहों के कुतरे हुए पाव के पैकेट मिले



प्रतिनिधि द्वारा - गांधीनगर गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फूड सेफ्टी ब्रांच ने 21/08/2026 को 7 छोटे-बड़े होटलों और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत किया गया, जिसमें खाने-पीने की चीजों की क्वालिटी की जांच की गई। एक्ट के तहत साफ-सफाई और हाइजीन से जुड़े नियमों (शेड्यूल-4) के आधार पर किए गए निरीक्षण में, साफ-सफाई और हाइजीन की स्थितियों में

हाइजीन की स्थिति ठीक नहीं पाई गई; किचन में गंदगी मिली और पाव के पैकेट चूहों द्वारा कुतरे हुए पाए गए। इसलिए, इसके फूड रजिस्ट्रेशन को 7 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और उस फर्म को बंद कर दिया गया है। अगर कोई सुधार नहीं दिखता है, तो आगे सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, रक्षा शक्ति सर्कल के पास स्थित ग्वालिया फूड फर्म में भी हाइजीन और साफ-सफाई की स्थितियों में कमियां पाई गईं। वहां जिनी सेव, चवणू आदि जैसे एक्सपायर्ड फूड आइटम मिले, साथ ही 31 किलो अस्वच्छ आटा (जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये थी) मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया और उस फर्म को सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया। एक अन्य फर्म, राजवी फूड कॉर्नर को भी साफ-सफाई और हाइजीन की स्थितियों की जांच के दौरान, पट्टी वड़ा पाव नाम की फर्म में साफ-सफाई और

जांच के दौरान, खाने की अलग-अलग चीजों के कुल 10 सैंपल लिए गए हैं। इनमें सरगासन के ला क्रस्ट होटल से पनीर शशालिक सिज़लर, मिल्केन मलाई पनीर और कच्चा माल जैसे तुअर दाल, मैदा, देगी मिर्च पाउडर और काला नमक पाउडर शामिल हैं। साथ ही, कुडासन के राजवी फूड कॉर्नर से अमूल मलाई पनीर और वेज मक्खनवाला रेडी सब्जी, और रक्षाशक्ति सर्कल के ग्वालिया फूड्स से मिक्स वेज रेडी फूड और दही के सैंपल भी लिए गए हैं। इनकी एनालिसिस रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, सभी जगहों पर अच्छी क्वालिटी और सेहतमंद खाना परोसा जाए, यह पक्का करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 और इसके तहत बने सभी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।



बुजुर्गों और बीपी, डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियों वाले मरीजों के लिए सबसे ज्यादा होता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने पर निकलने वाली बारीक बूंदों या संक्रमित सतह के संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। डॉक्टरों ने लापरवाही न बरतने की अपील की है, खासकर अगर किसी ऐसे व्यक्ति में बुखार, सर्दी या खांसी जैसे लक्षण दिखें जो गांव या देश के बाहर किसी राज्य की यात्रा से लौटा हो। साथ ही, अगर दो दिनों तक सेहत में सुधार न हो, तो तुरंत रिपोर्ट

करनी चाहिए और सही इलाज शुरू करना चाहिए। डॉक्टरों ने बिना काम के भीड़-भाड़ वाली जगहों पर न जाने की भी अपील की है, और अगर जाएं तो मास्क और दस्ताने पहनें और साफ-सफाई का ध्यान रखें। स्वाइन फ्लू के लक्षण अचानक बुखार और ठंड लगना गले में खराश या सूजन सिर और मांसपेशियों में तेज़ दर्द थकान और कमजोरी सांस लेने में कठिनाई चक्कर आना

ओलंपिक-कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों की समीक्षा होगी

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को फिर गुजरात का दौरा करेंगे

एजेंसी - अहमदाबाद, केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को गुजरात का दौरा करेंगे। गुजरात दौरे के दौरान, अमित शाह अमरेली में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद, अहमदाबाद और गांधीनगर में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकें होंगी। अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इन बैठकों में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी। खेल क्षेत्र में योजना, बुनियादी ढांचे की सुविधाओं और आगामी तैयारियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की संभावना है। गुजरात दौरे के दौरान, अमित शाह

अमरेली में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद, वह अहमदाबाद और गांधीनगर में कुछ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकें करेंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इन विशेष बैठकों में आगामी ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों पर गहराई से चर्चा और समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में पूरी संभावना है कि खेल क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य आगामी तैयारियों के संबंध में संबंधित उच्च अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की जाएगी। केन्द्रीय मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद में लोगों से सीधे बातचीत भी करेंगे। वह 27 अगस्त को अंबली-बोपल

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने घोषणा की

कोदिनार को गुजरात का श्रीहरिकोटा बनाने की तैयारी शुरू

एजेंसी - कोदिनार, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अंतरिक्ष क्षेत्र को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने कोदिनार के पास एक नया स्पेस लॉन्च स्टेशन या स्पेसपोर्ट बनाने की घोषणा की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अजुन मोडवाडिया ने 21 अगस्त को अहमदाबाद के साइंस सिटी में तीन दिवसीय स्पेस फेस्टिवल के उद्घाटन के दौरान यह घोषणा की। कोदिनार के पास स्पेसपोर्ट बनाने का काम अभी शुरुआती चरण में है। राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से साइट का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। साइट तय होने के बाद, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया जाएगा। कोदिनार और गिर के बीच का तटीय इलाका पहले भी अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों के लिए संभावित जगह के तौर पर चर्चा में रहा है। यहां की भौगोलिक स्थितियों और समुद्री इलाके के कारण रॉकेट

लॉन्च की संभावना का आकलन किया जा रहा है। हालांकि, प्रोजेक्ट की अंतिम जगह और तकनीकी विवरण अभी तय होने बाकी हैं। अभी, भारत का मुख्य स्पेसपोर्ट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, जबकि तमिलनाडु के कुलसेकरपड़िम में दूसरे स्पेसपोर्ट पर काम चल रहा है। अगर गुजरात में कोदिनार के पास प्रस्तावित लॉन्च सेंटर शुरू हो जाता है, तो राज्य देश के बढ़ते प्राइवेट और कमर्शियल स्पेस सेक्टर से और मजबूती से जुड़ सकता है। राज्य में अंतरिक्ष गतिविधियों, जिसमें सैटेलाइट बनाना भी शामिल है, को बढ़ावा देने के लिए खास पहल की जा रही है। अहमदाबाद में आंध्र-जिंचहरी का मुख्यालय भी है। इसके अलावा, अहमदाबाद के पास खोराज में स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए एक खास जोन विकसित करने पर भी काम हो रहा है। गुजरात में प्राइवेट सेक्टर की अंतरिक्ष गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। इस साल की शुरुआत में, धोलेरा के एक स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक अपना पहला सॉर्टिंग रॉकेट लॉन्च किया।

अनुमान है कि राज्य में स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में 20 से ज्यादा स्टार्टअप और संस्थान काम कर रहे हैं। भारत 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाता है। यह दिन 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की पूर्व संध्या पर गुजरात में एक स्पेसपोर्ट की घोषणा से अंतरिक्ष क्षेत्र में राज्य की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ावा मिल सकता है।

राजकोट घटना के बाद सीनियर डॉक्टर का पंचमहल तबादला

एजेंसी - राजकोट, राज्य सरकार ने राजकोट सिविल अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार की घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, सरकार महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने स्वास्थ्य विभाग को तत्काल और कानूनी कार्रवाई करने के स्पष्ट आदेश दिए हैं। जैसे ही पूरी घटना सामने आई, स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने पीडित महिला डॉक्टर से फोन पर बातचीत की। उन्होंने महिला डॉक्टर का हौसला बढ़ाया और उन्हें न्याय व पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। मंत्री

ने स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पतालों में महिला कर्मचारियों और डॉक्टरों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया के आदेश पर, राजकोट के आर.जेड. अस्पताल के डॉक्टर अश्विन रमानी का तबादला पंचमहल जिले के वावक डेली रिथत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाली हर महिला कर्मचारी और डॉक्टर की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या अनुचित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। मंत्री ने आगे कहा कि महिला डॉक्टर समाज को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। राज्य सरकार उनके लिए सम्मानजनक और सुरक्षित कार्यस्थल बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नियमों के अनुसार इस घटना में शामिल सीनियर डॉक्टर के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया के निर्देश पर, स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षित, सम्मानजनक और सकारात्मक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

कांतिभाई कई युवाओं के लिए प्रेरणा बने

वापी के पाटीदार दादा ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी फतह की

एजेंसी - वापी, वापी के साहसी पर्वतारोही कांतिभाई पटेल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक, माउंट एव्रस को सफलतापूर्वक फतह करके वापी सहित पूरे गुजरात राज्य का मान बढ़ाया है। माउंट एव्रस पर तिरंगा फहराकर उन्होंने अपनी साहसिक उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ी है। वापी के साहसी पर्वतारोही

कांतिभाई पटेल ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एव्रस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। 13 अगस्त 2026 को, उन्होंने समुद्र तल से 5,642 मीटर या 18,510 फीट की ऊंचाई पर स्थित माउंट एव्रस की चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। माउंट एव्रस रूस और यूरोप दोनों की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की सेवन समिट्स (सात चोटियों) में से एक है। इससे पहले, कांतिभाई पटेल ने 15 अगस्त 2024 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। कांतिभाई के लिए माउंट एव्रस की चढ़ाई चुनौतीपूर्ण थी। चढ़ाई के दौरान उन्हें लगातार बर्फबारी और तेज हवाओं जैसी मुश्किल स्थितियों का सामना करना पड़ा। चढ़ाई के दौरान तापमान गिरकर लगभग माइनस 10 डिग्री तक पहुंच गया था, जबकि हवा की वजह से ठंड का अहसास माइनस 35 डिग्री जैसा हो रहा था। इन मुश्किल हालात के बावजूद, कांतिभाई ने मजबूत इच्छाशक्ति और साहस के साथ माउंट एव्रस को फतह किया। वापी के चाला इलाके में अकेले रहने वाले कांतिभाई पटेल... 63 वर्षीय कांतिभाई, जो वापी की एक फार्मा कंपनी में मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे, 2014 में अपनी पत्नी के निधन के बाद अकेला जीवन जी रहे थे। हालांकि, रिटायरमेंट के बाद भी वे सक्रिय रहे और अपने शौक से युवाओं को भी पीछे छोड़ दिया। ट्रेकिंग और साइकिलिंग के शौकीन कांतिभाई ने इस उम्र में भी एक पर्वतारोही के तौर पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। 67 वर्षीय कांतिभाई को ट्रेकिंग का बहुत शौक है। उन्होंने साइकिलिंग में भी कई रिकॉर्ड बनाए हैं। पिछले 3 वर्षों में उन्होंने